POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2021/अंक 12

मासिक प्रेषण दि. 8 दिसम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 दिसम्बर, 2021 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! मुझे गर्व है ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में भारत की 14 साल की किशोरी विनिशा उमाशंकर पर, जिसने दुनिया के शक्तिशाली नेताओं को खरी-खरी सुनाते हुए बताया कि उसकी पीढ़ी 'दुनिया के नेताओं से नाराज और निराश है, जिन्होंने खोखले वादे किए हैं'।

विनिशा ने धरती को बचाने के लिए सीधा आह्वान करते हुए कहा कि जब जलवायु परिवर्तन की बात आती है, तो कोई 'स्टॉप बटन' नहीं होता। मेरी पीढ़ी के लोग नेताओं के ऐसे खोखले वादों से नाराज है जिन्हें पूरा करने में वे विफल रहे हैं। उसने कहा आप लोग भले ही अतीत में फंसे हों, लेकिन हम भविष्य बनाएंगे।

विनिशा के ऐसे दमदार भाषण से मुझे जून 1992 का वह दिन याद आ गया जब मैं ब्राजील के शहर रियो डि जेनेरियो में आयोजित 'पृथ्वी सम्मेलन' में मौजूद था। उस समय भी इसी तरह धरती के लिए बच्चों ने अपनी आवाज उठाई और कहा था 'हमने पृथ्वी को अपने मां-बाप से विरासत में नहीं पाया है, महज बच्चों से उधार लिया है! हमें पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण की सोच को विकसित करना होगा! ईश्वर ने हमें यह धरती उधार दी है, आने वाली पीढ़ियों को इसके उपकारों से वंचित न करें!'

उस वक्त बच्चों की इस दमदार और मार्मिक आवाज की रिपोर्ट मैंने 'राजस्थान पत्रिका' को भेजी थी। मुझे खुशी है पत्रिका ने तब मेरी हर दिन की रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। विनिशा ने इसे फिर दोहराया है। क्योंकि, यह एक सच्चाई है। दुनिया के दिग्गज और शक्तिशाली नेताओं की 'करनी और कथनी' में अंतर साफ झलकता है।

मेरा अब भी मानना है कि सभी देश मिलकर प्रकृति के रखवाले बनें और जलवायु परिवर्तन के बढ़ रहे दुष्प्रभावों को रोकने के लिए अपने कदम बढ़ाएं, तभी हम मानवता के भविष्य को बचा पाएंगे।

पीएनबी को देना होगा किसानों को फसल खराब होने का हर्जाना

फसल बीमा अनिवार्य होने के बावजूद पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने ओलावृष्टि से 2013 में खराब हुई सरसों व गेहूं की फसल का मुआवजा प्रभावित किसानों को देने से मना कर दिया। जबकि राज्य सरकार की रिपोर्ट में 58 फीसदी फसल को नुकसान होना माना गया। मामले के अनुसार, भरतपुर जिले की पहाड़ी तहसील के बहुत सारे किसानों को पीएनबी ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी कर रखे थें। योजना के तहत बीमा प्रीमियम राशि काटने और नियमानुसार कार्ड धारक किसानों का अनिवार्य फसल बीमा कराने की जिम्मेदारी बैंक की थी। लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया।

किसानों ने वकील राजीव गोठी के जरिए बैंक तथा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दर्ज कराया। मामले की सुनवाई के दौरान बैंक तथा इंश्योरेंस कंपनी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने माना कि बीमा प्रीमियम राशि काटने और अनिवार्य बीमा कराने की जिम्मेदारी बैंक की थी। आयोग ने पीएनबी को आदेश दिया कि वह प्रभावित 17 किसानों को गिरदावरी रिपोर्ट और बीमा योजना के मापदंडों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करके उस पर जुलाई 2013 से 6 फीसदी सालाना ब्याज के साथ मुआवजा राशि अदा करे। साथ ही प्रत्येक किसान को 10 हजार रुपए बतौर हर्जे-खर्चे का भुगतान भी किया जाए।

पीयूष शर्मा 'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित

'कट्स' द्वारा वर्ष 2002 से हर साल ग्रामीण पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के मकसद से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष उन श्रेष्ठ पत्रकारों को दिये जाते रहे हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जनहित के मामलों को असरदार तरीके से उठाया है।

इस बार वर्ष 2020 के लिए यह पुरस्कार 'कट्स' द्वारा 'अच्छे मददगार (गुड समेरीटन) संबंधी दिशा निर्देशः चुनौतियां एवं आगे की राह' विषय पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान महेन्द्र सोनी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, राजस्थान सरकार द्वारा बूंदी जिले के पत्रकार पीयूष शर्मा को प्रशस्ति पत्र एवं 10 हजार रुपए का चैक प्रदान कर सम्मानित किया गया।

पीयूष शर्मा बूंदी जिले के केशोराय पाटन गांव के मूल निवासी हैं तथा हलधर टाइम्स से जुड़े हुए हैं। उन्होंने वर्ष 2020 के दौरान 'कोरोना महामारी के दौरान बढ़ती बेरोजगारी' पर कई रोचक एवं तार्किक स्टोरियां प्रकाशित कर आमजन में जागरूकता लाने एवं जनचेतना जागृत करने का काम किया है।

प्रदेश में गुड समेरिटन के लिए जन जागरूकता जरूरी-बीजू जोसफ जॉर्ज

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को यदि तुरंत चिकित्सा मिल जाए तो उसका जीवन बचाया जा सकता है। जो भी व्यक्ति 'अच्छे मददगार'(गुड समेरिटन) के रूप में घायल व्यक्ति की मदद करता है, उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाए।

'कट्स' द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता से जयपुर में 'गुड समेरिटन गाइडलाइन्सः चैलेंज एण्ड वे फारवर्ड' पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में बीजू जोसफ जॉर्ज, एडिशनल डाइरेक्टर जनरल, पुलिस सतर्कता, राजस्थान ने विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए यह बताया। उन्होंने बताया कि राज्य में 2020 के दौरान 19,114 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें करीब 9200 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इनमें से 50 प्रतिशत लोगों को बचाया जा सकता था, यदि उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया होता।

कार्यक्रम में विशेष अतिथि महेन्द्र सोनी, आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि पुलिस विभाग सभी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निरंतर काम कर रही है। इसके लिए सड़क सुरक्षा से संबंधित कई गतिविधियां आयोजित की जाती है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाना हम सभी का दायित्व होना चाहिए।

कार्यशाला के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने गुड समेरिटन को परिभाषित करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 'कट्स' द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से राज्य के अजमेर, कोटा, जयपुर और उदयपुर में गुड समेरिटन के प्रति आम लोगों को जागरूक बनाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई है। अभी भी प्रदेश में 80 फीसदी लोगों में गुड़ समेरिटन गाइडलाइन की पूरी जानकारी का अभाव है। डॉ. नरोत्तम शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम ने सुझाव दिया कि सरकार को शिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूली पाठ्यक्रम में गुड़ समेरिटन को भी विषय रूप में शामिल करना चाहिए।

तकनीकी सत्र के पहले 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से 'कट्स' द्वारा संचालित 'गुड़ समेरिटन' के अधिकार व दायित्वों, जागरूकता कार्यक्रमों और गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण दिया। 'कट्स' के मधुसूदन शर्मा ने तकनीकी सत्र का संचालन किया जिसमें संयुक्त परिवहन आयुक्त निधि सिंह एवं ट्रोमा केयर एक्सपर्ट डॉ. गिरधर गोयल एवं अन्य महानुभावों ने विभिन्न जानकारियां देकर लाभान्वित किया।

लेटलतीफी: मकान मिलना हुआ मुश्किल

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत प्रदेश के गांवों में इस साल के लिए चुने गए तीन लाख से भी अधिक परिवारों को लेटलतीफी के चलते मकान मिलना मुश्किल होगा। केंद्र सरकार से मिले 3.97 लाख आवासों की मंजूरी होने के बावजूद आवासों को स्वीकृत करने से पहले हर ग्राम पंचायत में लाभार्थियों की श्रेणीवार वरीयता निर्धारित होनी है।

प्रदेश की 11 हजार से अधिक पंचायतों में से तकरीबन 8 हजार पंचायतों में यह वरीयता सूची पूरी तरह तैयार ही नहीं हो पाई है। सरकार ने जल्द वरीयता तय करने के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन प्रक्रिया देखते हुए यह कार्य इतना आसान नहीं दिख रहा है।

पैकेटबंद चीजों से सेहत को खतरा

पैकेट बंद जंक फूड का दखल शहरों में ही नहीं बल्कि सुदूर गांवों तक है। बच्चे इन खाद्य पदार्थों की आक्रामक विज्ञापन नीति से प्रभावित हैं। वे इनका अत्यधिक सेवन कर रहे हैं। इससे बच्चों में मोटापे की समस्या और उसकी वजह से वयस्क होने पर डायबिटीज, हार्ट, ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियों का जोखिम बढ़ रहा है।

भारतीय अभिभावक भी अब खाने-पीने की पैंकेटबंद चीजों से सेहत पर पड़ने वाले खतरे को लेकर काफी सजग हो रहे हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 80 प्रतिशत माता-पिता चाहते हैं कि खाने-पीने की पैकेटबंद सामग्री पर ऊपर की ओर आसानी से समझ आने वाले तरीके से चेतावनी लिखना अनिवार्य हो। पैकेट पर वसा, नमक व चीनी आदि की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण को लोगों की सेहत के पक्ष में खड़ा होना चाहिए।

प्रदेश में नहीं बन पा रहे किसान ऊर्जादाता

प्रदेश में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को बंजर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने की योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही। प्रदेश के 623 किसानों ने अपनी बंजर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने में खूब रुचि दिखाई है। लेकिन बैंक उन्हें लाखों रुपए का ऋण देने के लिए तैयार नहीं है। योजना के दूसरे साल में महज आठ प्लांट लग पाए हैं।

स्थिति यह है कि कंपनियां किसानों से भूमि खरीदकर या बीस पच्चीस साल के लिए लीज पर लेकर सोलर प्लांट लगाकर बिजली सरकार को बेचती है। इससे किसान की भूमि कंपनियों की गिरफ्त में आने की आशंका बन रही है। योजना के मुताबिक किसान खुद ऊर्जादाता बनकर अतिरिक्त आय सृजन नहीं कर पा रहे हैं।

मोटा अनाज से होता है 36 रोगों का इलाज

देहाती और गरीबों का भोजन समझ कर जिन मोटे अनाजों को रसोई से बाहर कर दिया गया, आज वैज्ञानिक और डॉक्टर लोगों को उन अनाजों को खाने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि यदि देश में मोटा अनाज फिर से चलन में आ जाए तो 70 फीसदी लोग कुपोषण से मुक्त हो जाएंगे।

इसके साथ ही लोग मोटापा, बदहजमी, डॉयबिटीज, एनिमिया, हार्ट और कोलेस्ट्राल जैसी 36 बीमारियों से भी मुक्त हो सकते हैं। जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना जैसे कई मोटे अनाजों में कैलशियम, प्रोटीन, जिक, मैग्नीज, आइरन, खनिज तत्व, फोलिक ऐसिड, विटामिन-बी ई और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। गौरतलब यह है, देश में 88 करोड़ लोगों को गेहूं और चावल के साथ सरकार मोटा अनाज क्यों नहीं बांट रही?

गांव-ढाणियों में हर घर पेयजल कनेक्शन

प्रदेश में मौजूदा वित्तीय वर्ष में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को 'हर घर नल कनेक्शन' देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक 1077 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मिशन के तहत गांव-ढाणियों में नल कनेक्शन देकर 10 नवम्बर तक प्रदेश के 43 हजार 323 गांवों में से 35 हजार 955 गांवों के एक्शन प्लान तैयार कर लिए गए हैं।

देश में सर्वाधिक विलेज एक्शन प्लान तैयार करके राजस्थान सबसे अग्रणी राज्य बन गया है। राज्य में पिछले दो सालों में 11 लाख 74 हजार घरों में नल कनेक्शन किए गए। सबसे ज्यादा कनेक्शन राजसमंद, हनुमानगढ़, पाली, नागौर और जयपुर में हुए हैं।

सशक्तिकरण की मिसाल बनी महिलाएं

राजस्थान के सीकर जिले में स्थित नीमकाथाना और श्रीमाधोपुर क्षेत्र की ग्रामीण महिलाएं पुश्तैनी रोजगार एवं संस्कृति के साथ पिछले कई सालों से महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी हुई हैं। यहां के करीब 15 गांवों में सैंकड़ों महिलाएं गलीचे निर्माण के पुश्तैनी काम को आगे बढ़ा रही हैं।

खास बात यह है कि यहां सास अपनी बहुओं को घर की परंपराओं के साथ लूम पर गलीचा बनाई का काम सिखाती है। जिससे यह लघु उद्योग पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। इस काम के लिए महिलाएं घरेलू कार्यों में से समय निकालती हैं। यहां तैयार होने वाले गलीचे देश ही नहीं विदेशों में अमरीका और यूरोप तक जाते हैं। इस परंपरा के चलते इन गांवों की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रही हैं।

जलवायु शिखर सम्मेलन

मोदी ने दिया जागरूकता पर जोर

ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 'कोप-26' के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगली पीढ़ी को जागरूक बनाने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में जलवायु नीतियों को शामिल करने की जरूरत है। भारत 2070 तक कार्बन उत्सर्जन 'शुद्ध शून्य' का लक्ष्य हासिल कर लेगा।

मोदी ने कहा कि औद्योगिक क्रांति ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़कर पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हम सूर्य के माध्यम से प्रकृति से फिर से जुड़कर मानवता के भविष्य को बचा सकते हैं। मोदी ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के साथ संयुक्त रूप से 'एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड' की पहल शुरू करते हुए यह बात कही। उन्होंने एक ओर महत्वपूर्ण घोषणा भी की कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो जल्द ही एक ऐसा सौर कैलकुलेटर बनाने जा रही है, जो किसी भी जगह की सौर ऊर्जा संभावनाओं को नाप सकेगा।

धरातल पर नहीं उतरे रोजगार देने के वादे

प्रदेश में कोरोना की पहली व दूसरी लहर के दौरान सरकार की ओर से प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के वादे तो खूब किए, लेकिन जमीनी स्तर पर इनकी स्थिति कागजी साबित हुई। सरकार ने कामगारों को कौशल विकास निगम व स्वयं सहायता समूहों के जरिए प्रशिक्षण दिलाने का दावा किया, लेकिन प्रदेश के 12 लाख से अधिक कामगार योजना शुरू होने का इंतजार करते रहे।

गौरतलब है कि कौशल विकास निगम के अधिकारी व कर्मचारी फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार में अपना कौशल दिखाने में लगे रहे। जिससे अभी तक भी प्रशिक्षण केंद्र ही शुरू नहीं हुए। सरकार ने कामगारों के लिए ऋण दिलाने का वादा भी किया लेकिन उसमें भी कामगारों को राहत नहीं मिली।

स्वयं सहायता समूह बना सक्षमता का मंत्र

चूल्हे-चौके में उलझी रहने वाली महिलाएं अब बिजली मीटर रीडिंग कर रही हैं, स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म सिल रही हैं, ऑक्सीजन प्लांट का संचालन कर रही हैं। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट, खिलौने, सिलाई-कढ़ाई, मास्क निर्माण जैसे कई काम कर आर्थिक आजादी महसूस कर रही हैं। साथ ही वंचित, शोषित आदिवासी वर्ग भी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है।

यह सब हो रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए। इसके तहत स्वयं सहायता समूह बनाकर लोग सक्षम हो रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। देश में 72 लाख 78 हजार से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485